Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

31st AUGUST 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

31st August 2022

1. - गर्भपात कानूनों का विवरण:.....3
   (i) भारत में गर्भपात प्रतिबंध तब से हैं:.....3
   (ii) 1971 से 2021 तक एमटीपी का विकास:.....3
   (iii) गर्भपात से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप:.....4
   (iv) गर्भपात विरोधी क़ानून के निम्नलिखित औचित्य हैं:.....4
   (v) निष्कर्ष:.....5

2. - नक्सलवाद का विवरण:.....6
   (i) भारतीय नक्सली आंदोलन:.....6
   (ii) कारण:.....6
   (iii) पर्यावरण का बिगड़ना:.....7
   (iv) महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का अभाव:.....7
   (v) नक्सलियों के साथ युद्ध के दौरान सीआरपीएफ को निम्नलिखित झटके लगे:.....7
   (vi) सरकार की रणनीति:.....7
   (vii) आकांक्षी जिलों के लिए कार्यक्रम:.....7
   (viii) आगे बढ़ने के लिए कदम:.....8
   (ix) वर्तमान कानून प्रवर्तन संगठन:.....9
   (x) कैसे आगे बढ़ें:.....9

3. - भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के बारे में:.....10
   (i) के बारे में:.....10
   (ii) पेलोड:.....10

(iii) मिशन में रूसी भूमिका: 10

(iv) महत्त्व: 10

4. - एलओसी का विवरण: 12

(i) एलओसी के बारे में: 12

(ii) एलओसी पर वाणिज्य और व्यापार: 12

संपादकीय विश्लेषण 13

1. एफएटीएफ के बारे में सब कुछ: 13

(i) के बारे में: 13

(ii) FATF के कर्तव्यों में शामिल हैं: 13

(iii) फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का एक लंबा इतिहास रहा है: 13

(iv) सदस्य: 13

(v) FATF के लक्ष्य इस प्रकार हैं: 14

(vi) FATF की सिफारिशों को व्यवहार में लाना: 14

(vii) पाकिस्तान: 14

(viii) राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने रेखांकित किया है: 14

2. एससीओ के बारे में: 15

(i) के बारे में: 15

(ii) मूल: 15

(iii) उद्देश्य: 15

(iv) सदस्यता: 15

(v) संरचना: 15

(vi) एससीओ सचिवालय में प्रयुक्त भाषाएँ: 15

1. - गर्भपात कानूनों का विवरण:

जीएस II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

भारत में गर्भपात प्रतिबंध तब से हैं:

- 1960 के दशक में प्रेरित गर्भपात की आवृत्ति बढ़ने के साथ, केंद्र सरकार ने देश में गर्भपात को कानूनी बनाने की व्यवहार्यता की जांच के लिए शांतिलाल शाह समिति की स्थापना की।
- असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम बनाया गया था।
- जिन परिस्थितियों में चिकित्सीय गर्भपात किया जा सकता है, उन्हें इस कानून में निर्धारित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 इस पर (आईपीसी) लागू नहीं होती।
- जब तक वे गर्भवती महिला के जीवन को संरक्षित करने के प्रयास में अच्छे विश्वास में व्यवहार नहीं करते, कोई भी जो "स्वेच्छा से गर्भपात के लिए बच्चे के साथ एक महिला को प्रेरित करता है" को अधिकतम तीन साल की जेल की सजा, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ता है।
- यह खंड अनिवार्य रूप से भारत में सभी गर्भपात को गैरकानूनी घोषित करता है।
- महिला चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, गर्भवती महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 313 के तहत दंड के अधीन है, जिसमें जुर्माना, आजीवन कारावास या अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

1971 से 2021 तक एमटीपी का विकास:

- एमटीपी अधिनियम ने 2021 में अपना सबसे हालिया संशोधन किया।
- इससे पहले के वर्षों में, मिसोप्रोस्टोल के उपयोग की अनुमति देने के लिए 2003 में नए नियम लागू किए गए थे, जो एक ताजा खोजी गई गर्भपात दवा है, ताकि गर्भावस्था को सात सप्ताह तक समाप्त किया जा सके।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 उन शर्तों को बताता है जिनमें चिकित्सक की सलाह पर गर्भपात कानूनी है।
- 2021 के अधिनियम के आधार पर, अधिकतम गर्भावधि अवधि जिस पर एक महिला चिकित्सकीय गर्भपात से गुजर सकती है, उसे 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।
- यह अद्यतन ऊपरी सीमा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती है।
- गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक, एमटीपी अब एकल लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा प्रदाता की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- 20 से 24 सप्ताह के बीच दो लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता होती है।
- गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक के चिकित्सीय गर्भपात के लिए अधिनियम के पिछले संस्करण के तहत एक पंजीकृत चिकित्सक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जबकि 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए दो डॉक्टरों की सहमति की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, अधिनियम के अनुरूप प्रत्येक राज्य में स्थापित चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पर गर्भधारण के 24 सप्ताह के बाद ही गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।

- उपरोक्त किसी भी प्रतिबंध के बावजूद, कानून यह भी प्रदान करता है कि गर्भवती महिला के जीवन को संरक्षित करने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर द्वारा जब भी आवश्यक हो गर्भपात किया जा सकता है।
- 2021 के अधिनियम में पति-पत्नी की सहमति की आवश्यकता की कमी के कारण, अविवाहित महिलाओं का भी उपरोक्त शर्तों को देखते हुए गर्भपात हो सकता है। यदि महिला नाबालिग है, तो माता-पिता की अनुमति आवश्यक है।

गर्भपात से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप:

- गर्भावस्था को जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक गर्भवती व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ-साथ उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ऐतिहासिक निजता के अधिकार के फैसले में फैसला सुनाया। मामला न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य। एक 37 वर्षीय महिला के 34 सप्ताह के गर्भ में चिकित्सकीय गर्भपात के अनुरोध को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद स्वीकार कर लिया कि देश के मौजूदा कानून बिना शर्त गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं। यह देखते हुए कि भ्रूण की रीढ़ की विकृति लाइलाज होने की पुष्टि की गई थी, ऐसा किया गया था।
- स्टेट मेडिकल बोर्ड द्वारा एमटीपी के लिए महिला के आवेदन को खारिज करने के बाद कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया।
- इस निर्णय के कारण, देश में प्रसव के बिंदु तक गर्भपात की अनुमति थी।

गर्भपात विरोधी क़ानून के निम्नलिखित औचित्य हैं:

- लैंसेट में प्रकाशित 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, 2015 तक, भारत में सालाना 15.6 मिलियन गर्भपात हुए थे।
- हाल ही के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–2021 के अनुसार, माँ ने घर पर 27% गर्भपात किया।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 की स्थिति के अनुसार, असुरक्षित गर्भपात के कारण भारत में हर दिन 8 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है (यूएनएफपीए)।
- एमटीपी अधिनियम के अनुसार, केवल स्त्री रोग विशेषज्ञों या प्रसूति रोग विशेषज्ञों को गर्भपात करने की अनुमति है।
- हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2019–20 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है।
- आलोचकों का दावा है कि चूंकि कानून किसी भी समय गर्भपात को प्रतिबंधित करता है, इसलिए यह महिलाओं को खतरनाक, अनधिकृत गर्भपात करने के लिए मजबूर करता है।
- आंकड़ों के अनुसार, भारत प्रति वर्ष 80,000 असुरक्षित और अवैध गर्भपात करता है, जिनमें से कई के परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु होती है।
- चूंकि "महिला" शब्द का प्रयोग कानून में किया जाता है, इसलिए गर्भवती ट्रांसजेंडर और गैर-बाइनरी लोग जो चिकित्सकीय रूप से बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
- उन पर अपनी मूल लिंग पहचान के स्थान पर लिंग-द्विआधारी पहचान अपनाने का दबाव डाला जाता है।

- वहनीयता और सामाजिक कलंक जो असुरक्षित गर्भपात को प्रोत्साहित करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं।
- केवल पर्याप्त वित्तीय साधनों वाले लोगों के पास गर्भपात करने वाली महंगी निजी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच है।

निष्कर्ष:

- भारत का परिदृश्य आदर्श से बहुत दूर है, इसलिए अत्याधुनिक वैश्विक प्रथाओं पर विचार करना और उन्हें लागू करना महत्वपूर्ण है।
- विविधता, पूर्ण शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन निष्पक्षता हमारे लक्ष्य होने चाहिए।
- हमें पीछे हटने की दर के खिलाफ अपनी प्रगति का आकलन करके राष्ट्र का प्रबंधन शुरू नहीं करना चाहिए।
- शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों का मूल्यांकन करते समय कानूनी, चिकित्सा और सामाजिक विचार किए जाने चाहिए।
- यह कहना असंभव है कि भारत पश्चिम का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जब तक कि महिलाओं और गैर-बाइनरी गर्भवती लोगों का इन मूल्यों के अनुसार अपने स्वयं के शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

2. - नक्सलवाद का विवरण:

जीएस III

विषय→भारत की आंतरिक सुरक्षा

भारतीय नक्सली आंदोलन:

- आंदोलन के शुरुआती चरणों को चारु मजूमदार, कोंडापल्ली सीतारमैया, नागभूषण पटनायक, और इसके नेताओं के रूप में सेवा करने वाले अन्य लोगों की ओर से मजबूत वैचारिक प्रेरणा द्वारा चिह्नित किया गया था।
- आंदोलन का फोकस और व्यक्तित्व समय के साथ बदल गया, और अधिक क्रूर और प्रफुल्लित हो गया।
- हालांकि, इसने अभी भी इस विचार को त्याग दिया कि यह वंचितों और वंचितों, विशेषकर आदिवासी लोगों के लिए ईमानदारी से लड़ रहा था।
- माओवाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सबसे अधिक वैचारिक रूप से समर्पित क्षेत्रों के साथ गूंज रहा है, जबकि शहरी बुद्धिजीवियों का कुछ समर्थन खो रहा है।
- छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों के लिए वर्तमान हॉटस्पॉट दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर और सुकमा हैं।
- प्रारंभिक काल (1967-1972) और वर्तमान माओवादी आंदोलन के बीच नक्सलवाद के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- यह अब एक अत्यधिक संगठित, सैन्यवादी आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है जो अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक आबादी को आतंकित करने को प्राथमिकता देता है।
- ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड द्वारा एक समन्वित ऑपरेशन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के लगभग 30 कैडरों की लागत आई।
- कई लोगों का मानना है कि यह देश में नक्सली आंदोलन के खात्मे की शुरुआत थी।

कारण:

राजनीतिक घटक:

- इस तरह के विद्रोह के मुख्य कारणों में आदिवासी लोगों के लक्षण और उनके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की अवमानना थी।
- भारत में राजनीतिक प्रभाव का अभाव प्रभावित राज्यों में समाज के वंचित वर्गों को संरचनात्मक उत्थान के अवसर प्राप्त करने से रोकता है।
- जनजातीय समूह राजनीति में पर्याप्त रूप से भाग नहीं लेते हैं।

आर्थिक चर:

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विषमता, अल्पविकास और गरीबी है।
- आदिवासी भूमि और जंगल में खनन फर्मों का आक्रमण उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है।
- मूल आदिवासी आबादी को उनके भोजन के पारंपरिक स्रोतों से काट दिया गया और उनके प्रदेशों को लूट लिया गया
- स्वदेशी समुदाय को संसाधन निष्कर्षण से कोई लाभ नहीं होता है।

पर्यावरण का बिगड़ना:

- खनन और औद्योगिक गतिविधि पानी और भूमि संसाधनों की कमी के रूप में पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनती है।

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का अभाव:

- स्वच्छता, स्वतंत्रता, भोजन और स्वतंत्रता सहित आवश्यक सेवाओं तक खराब पहुंच।
- असमानता, अज्ञानता और अवसरों की कमी के कारण, सामाजिक रूप से वंचित आदिवासी नक्सलियों के समर्थन आधार का बहुमत बनाते हैं।

नक्सलियों के साथ युद्ध के दौरान सीआरपीएफ को निम्नलिखित झटके लगे:

- राज्यों के पास एक भी रणनीति नहीं है।
- केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के बीच अपर्याप्त संचार है।
- माओवादी प्रभावित राज्यों में बलों के बीच आवश्यक युद्ध तत्परता और प्रशिक्षण की कमी है।
- राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक औपचारिक ढांचा अभी तक मौजूद नहीं है।
- सशस्त्र संघर्ष में, नक्सलियों को क्षेत्र से परिचित होने के कारण बहुत बड़ा फायदा होता है।

सरकार की रणनीति:

- 2010 में शुरू हुए ऑपरेशन ग्रीन हंट के हिस्से के रूप में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों को भारी मात्रा में तैनात किया गया था। 2010 में, नक्सलवाद से त्रस्त 223 जिले थे; आज, केवल 90 हैं।

आकांक्षी जिलों के लिए कार्यक्रम:

- सुरक्षा, विकास, स्थानीय आबादी के अधिकारों और अधिकारों के संरक्षण, बेहतर शासन और सार्वजनिक धारणा प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार की रणनीति व्यापक है।
- चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारें मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
- उन राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे की योजना को लागू करना जहां वामपंथी उग्रवाद गंभीर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए एक समस्या है।
- रक्षा मंत्रालय राज्य पुलिस प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने वाली पहलों के लिए समर्थन।
- खतरे को यथाशीघ्र रोकने के लिए, "वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" है।
- राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीकृत बलों की तैनाती में सुधार करना वामपंथी उग्रवाद विरोधी (एलडब्ल्यूई) नीति का लक्ष्य है।

आगे बढ़ने के लिए कदम:

अनुकरणीय नेतृत्व की आवश्यकता है:

- देश में नक्सलियों की मौजूदगी कानूनी व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करती है, जो खतरे को रोकने में नाकाम रही है.
- नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए, संघीय सरकार को एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए।

लगातार संवाद:

- नक्सल नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा से कोई हल निकल सकता है।
- सरकार द्वारा नक्सलियों को बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

वेतन बढ़ाकर रोजगार को बढ़ावा दें:

- क्षेत्र में अनियमित नौकरी और रहने की स्थिति के कारण ग्रामीणों के पास नक्सलियों में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
- यदि हमें नक्सलवाद का सफलतापूर्वक मुकाबला करना है, तो हमें पहले स्थानीय समुदाय को ईमानदार, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए अवसर प्रदान करने होंगे।

पुनर्वास और पुनर्वास की योजनाएँ:

- क्षेत्र में खनन मैदानों, सिंचाई क्षेत्रों, उद्योगों आदि की उपस्थिति के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए किसी भी योजना की कमी ने गरीब लोगों की दुर्दशा को ही बदतर बना दिया है।
- प्रभावित आबादी के पुनर्वास पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण के विनाश को रोकें:

- औद्योगिक और खनन गतिविधियों के परिणामस्वरूप जल और भूमि संसाधनों की कमी के कारण पर्यावरणीय गिरावट
- ग्रामीण जीवन की अशांति पर्यटन उद्योग के लिए बुरी है।

वंचित समूहों के राजनीतिक हाशिए पर जाने से बचें:

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निम्न वर्ग को शासक वर्ग से असमान व्यवहार मिलता रहता है।
- ये हाशिए की आबादी नक्सलियों के लिए आसान लक्ष्य हैं क्योंकि वे राजनीतिक चुनावों और अभियानों में समान रूप से भाग नहीं लेते हैं।

विसंगति कम करें:

- आर्थिक असमानता और बढ़ता धन अंतर दो प्राथमिक कारक हैं जिन्होंने नक्सलवाद के उदय में योगदान दिया है।
- नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए इस अंतर को जल्द से जल्द आंशिक रूप से पाटना होगा।

सुनिश्चित करें कि आम लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों:

- औद्योगिक हितों के लिए जनजातीय भूमि और जंगलों का उपयोग अस्थिरता के मुख्य कारणों में से एक है।

- भोजन, स्वच्छ पानी, स्वतंत्रता, और शिक्षा के साथ-साथ भूमि की हानि सहित आवश्यकताओं तक पहुंच का अभाव

स्वदेशी लोगों के कल्याण में सुधार के लिए कदम उठाएं:

- अन्याय, अज्ञानता और अवसरों की कमी के कारण, नक्सलियों के अधिकांश समर्थक आदिवासी व्यक्ति हैं जो सामाजिक रूप से वंचित हैं।
- इन लोगों को नक्सली जाल में पड़ने से रोकना बेहद जरूरी है।

वर्तमान कानून प्रवर्तन संगठन:

- राज्य सरकारें कानून प्रवर्तन के बहुमत के प्रभारी हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय कई संघीय एजेंसियों का प्रभारी है।
- संघीय सरकार को कभी-कभी कम संसाधन वाले राज्य अधिकारियों की सहायता करते हुए इन अस्थिर क्षेत्रों में जाना चाहिए। यह अपनी एजेंसियों को अत्याधुनिक तोपखाने से लैस करके ऐसा करता है।

कैसे आगे बढ़ें:

- प्रशासन, सुरक्षा प्रणाली, और संघीय और राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि आंदोलन को पूरी तरह से कानून और व्यवस्था के नजरिए से नहीं माना जा सकता है।
- यदि आंदोलन को सफलतापूर्वक रोकना है, तो यह स्पष्ट है कि वंचितों और स्वदेशी लोगों के जीवन में सुधार की प्रक्रिया को तेज करना होगा।
- जनजातीय आबादी और अन्य हाशिए के समूहों की सोच को बदलना आतंकवाद विरोधी अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा।
- सड़क और रेल नेटवर्क में सुधार से माओवादी प्रचार को दबाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- बेहतर सड़क संपर्क के परिणामस्वरूप सुरक्षा बल के संचालन की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

3. - भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के बारे में:

जीएस III

विषय→अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

के बारे में:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गगनयान मिशन (इसरो)।
- गगनयान समय सारिणी में तीन मिशनों को कक्षा में लॉन्च करने का आह्वान किया गया है।
- एक मानव और दो मानव रहित अंतरिक्ष मिशन होंगे।
- एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान सिस्टम मॉड्यूल पर यात्रा करेंगे, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है।
- यह ग्रह से 300-400 किमी ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में 5-7 दिन बिताएगा।

पेलोड:

- क्रू मॉड्यूल, एक अंतरिक्ष यान जो मनुष्यों को ले जाता है, कार्गो होगा।
- सर्विस मॉड्यूल पर स्थापित दो तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित।
- मिशन रद्द करने और आपातकालीन निकासी की सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।
- प्रक्षेपण: तीन चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके III, जिसे एलवीएम -3 (लॉन्च व्हीकल मार्क -3) के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग गगनयान को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा क्योंकि इसमें आवश्यक पेलोड क्षमता है।

मिशन में रूसी भूमिका:

- जून 2019 में, रूसी सरकार के Glavkosmos और ISRO के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के बीच प्रशिक्षण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आवेदक के चयन, चिकित्सा परीक्षण और अंतरिक्ष में प्रशिक्षण के साथ रूसी सहायता शामिल है।
- उम्मीदवार सोयुज मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के हार्डवेयर को करीब से देख सकेंगे और IL-76MDK जेट पर अल्पकालिक भारहीनता में कुछ अभ्यास प्राप्त करेंगे।
- रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज बनाया गया था। सोयुज कार्गो और लोगों को पृथ्वी और अंतरिक्ष स्टेशन के बीच बंद कर देता है।
- Il-76MDK नामक एक सैन्य परिवहन विमान स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों द्वारा परवलयिक उड़ानों के लिए बनाया गया था।

महत्त्व:

- युवा प्रेरित होंगे, और देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि होगी।
- गगनयान में विभिन्न विभागों, संगठनों, प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक विषयों और वाणिज्यिक उद्यमों को शामिल किया जाएगा।

- यह उद्योग के विस्तार का समर्थन करेगा।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने IN-SPACe नामक एक नए संगठन की स्थापना की है।
- यह सामाजिक सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएगा।
- यह वैश्विक सहयोग को बेहतर बनाने में योगदान देगा।
- केवल एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) होना पर्याप्त नहीं हो सकता है, जिसे कई अलग-अलग देशों द्वारा बनाया गया था। गगनयान भोजन, पानी और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होगी।

- ***स्रोत→ द साइंस रिपोर्टर***

GURU DEEKSHAA IAS

4. - एलओसी का विवरण:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

एलओसी के बारे में:

- 3 जुलाई 1972 के बाद, शिमला समझौते, "नियंत्रण रेखा", जिसे पहले "संघर्ष-विराम रेखा" के रूप में जाना जाता था, को एक नया नाम दिया गया था।
- जम्मू और कश्मीर राज्य जम्मू के उस हिस्से को दिया गया नाम है जो भारतीय अधिकार के अधीन है। गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू-कश्मीर पाकिस्तानी शासन के तहत स्वायत्त क्षेत्र हैं। नियंत्रण रेखा का सबसे उत्तरी बिंदु NJ9842 के रूप में जाना जाता है।
- अक्साई चिन का क्षेत्र, जो चीन द्वारा शासित है, और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर अभी तक एक और युद्धविराम रेखा से विभाजित हैं।
- नियंत्रण रेखा द्वारा कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसने झेलम घाटी तक पहुंच पर भी रोक लगा दी थी।

एलओसी पर वाणिज्य और व्यापार:

- जम्मू और कश्मीर में एलओसी वाणिज्य का उद्देश्य क्षेत्रीय समूहों के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का व्यापार करना आसान बनाना है।
- दो व्यापार सुविधा केंद्र- एक पुंछ के चक्कन-दा-बाग और सलामाबाद, उरी जिलों में-व्यापार की अनुमति देता है।
- केवल सप्ताह के उन चार दिनों में व्यापार की अनुमति है।
- *स्रोत→ हिन्दू*

संपादकीय विश्लेषण

1. एफएटीएफ के बारे में सब कुछ:

के बारे में:

- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी के प्रभारी बहुराष्ट्रीय संगठन को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) कहा जाता है।
- अंतर-सरकारी संगठन इन गैरकानूनी कार्यों को रोकने और समाज को होने वाले नुकसान को रोकने के इरादे से वैश्विक मानक बनाता है।
- FATF नीति-निर्माण निकाय के रूप में अपनी भूमिका के हिस्से के रूप में इस प्रकार के राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाने के लिए काम करता है।
- एफएटीएफ ने एफएटीएफ सिफारिशें बनाई हैं, जिन्हें अक्सर एफएटीएफ मानकों के रूप में जाना जाता है, ताकि आतंकवाद, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को सक्षम किया जा सके।
- वे उस धन का पता लगाने में कानून प्रवर्तन की सहायता करते हैं जिसका उपयोग अपराधी लोगों की तस्करी और अवैध दवाओं की बिक्री सहित अपराधों को अंजाम देने के लिए करते हैं।
- WMDs, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के वित्तपोषण को रोकने के लिए, FATF काम करता है।

FATF के कर्तव्यों में शामिल हैं:

- नए खतरों से निपटने के लिए FATF लगातार अपने नियमों को अपडेट कर रहा है. ऐसा ही एक क्षेत्र आभासी संपत्ति का विनियमन है, जो अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिप्टोक्यूरैंक्स लोकप्रियता हासिल करते हैं। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के तरीकों को भी देखता है।
- FATF यह सुनिश्चित करके गैर-अनुपालन वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराता है कि FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का एक लंबा इतिहास रहा है:

- मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में पेरिस में जी -7 शिखर सम्मेलन में अभ्यास के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में की गई थी।
- जी -7 राज्य या सरकार के प्रमुख और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों को टास्क फोर्स बनाने के खतरे को महसूस करने के बाद एक बैठक बुलाई, जिसमें जी -7 सदस्य राज्यों, यूरोपीय आयोग के सदस्य शामिल थे। , और आठ अतिरिक्त राष्ट्र।

सदस्य:

- 1991 और 1992 के बीच FATF की सदस्यता इसके मूल 16 से बढ़कर 28 हो गई। 2000 में FATF की स्थापना के समय 31 सदस्य थे; अभी तक, 39 हैं।

- अक्टूबर 2001 में 9/11 के हमलों के बाद, FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण दोनों से निपटने के लिए पहलों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया।
- इसने अप्रैल 2012 में WMD के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया।

FATF के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य जोखिमों से निपटने के लिए न्यायिक, प्रशासनिक और परिचालन प्रक्रियाओं के उचित उपयोग को दिशा प्रदान करना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

FATF की सिफारिशों को व्यवहार में लाना:

- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के उपायों और तरीकों की जांच करता है; दुनिया भर में FATF की सिफारिशों को अपनाने और लागू करने को प्रोत्साहित करता है।
- FATF प्लेनरी, जो FATF की देखरेख करती है, साल में तीन बार बुलाती है।
- FATF के 37 सदस्य देशों और दो क्षेत्रीय संगठनों में दुनिया के अधिकांश मुख्य वित्तीय केंद्र (GCC और यूरोपीय आयोग) शामिल हैं।
- 2010 से भारत FATF का हिस्सा है।
- भारत यूरेशियन ग्रुप (ईजी) और एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी), इसके दो क्षेत्रीय सहयोगी (ईएजी) का सदस्य है।

पाकिस्तान:

- 2008 में सूची से हटाए जाने से पहले, पाकिस्तान को शुरू में जोड़ा गया था। फिर, 2012 से 2015 तक, इसे एक बार फिर सूचीबद्ध किया गया।
- हालांकि इसे 2018 के बाद से सूची से हटाया नहीं गया है।
- जून 2018 में, FATF ने पाकिस्तान को अपनी "ग्रे लिस्ट" में डाल दिया, जिसके कारण 27-सूत्रीय कार्य योजना जारी की गई।
- कार्य योजना का उद्देश्य आतंकवादियों के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने 2019 (APG) में इसी तरह की कार्य योजना जारी की।

राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने रेखांकित किया है:

- जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी के तहत रखता है, तो यह इंगित करता है कि राष्ट्र किसी भी रणनीतिक कमजोरियों को जल्द से जल्द और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर सुधारने के लिए सहमत हो गया है।
- इस देश में, निगरानी को भी अधिक बार नियोजित किया जा रहा है।
- Greylisting विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करते हुए देश के आयात, निर्यात और प्रेषण को नुकसान पहुंचाता है।
- ग्रे लिस्ट में शामिल राज्यों को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंचने में परेशानी होती है, और आईएमएफ और विश्व बैंक एफएटीएफ के साथ मॉनिटर के रूप में जुड़े हुए हैं।

2. एससीओ के बारे में:

के बारे में:

- एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन के रूप में, एससीओ बनाया गया था।
- क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना इस यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संस्थान का लक्ष्य है।
- 2003 में, SCO चार्टर 2002 में अनुसमर्थन के बाद लागू हुआ।

मूल:

- शंघाई फाइव, जिसमें ताजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूस शामिल थे, 2001 में एससीओ की स्थापना से पहले मौजूद थे।
- सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए, चीन और चार पूर्व सोवियत गणराज्यों ने कई सीमा सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की, जिसके परिणामस्वरूप 1996 शंघाई फाइव हुआ।
- 2001 में, उज्बेकिस्तान शंघाई फाइव में शामिल हो गया, जिसने अंततः इसका नाम बदलकर SCO कर लिया।
- 2017 में पाकिस्तान और भारत शामिल हुए।

उद्देश्य:

- सदस्य राज्यों को एक साथ काम करने और अच्छे पड़ोसी बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
- व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और संस्कृति में कुशल सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- यात्रा, ऊर्जा, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में व्यवसायों के साथ संबंध स्थापित करना।
- क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना और बनाए रखना।
- एक नई, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तार्किक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण।

सदस्यता:

- नामित अन्य राष्ट्र ईरान, चीन, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान हैं।

संरचना:

- राज्य परिषद के प्रमुख, जो एससीओ की देखरेख करते हैं, यह तय करते हैं कि संगठन आंतरिक रूप से कैसे काम करेगा, अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत करेगा और वैश्विक चिंताओं का जवाब देगा।
- सरकार परिषद के प्रमुख एससीओ के भीतर आर्थिक क्षेत्रों की बातचीत से संबंधित बजट के साथ-साथ समस्याओं पर चर्चा और अनुमोदन करते हैं।
- आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) बनाई गई।
- बीजिंग में एससीओ सचिवालय द्वारा प्रशासनिक, विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

एससीओ सचिवालय में प्रयुक्त भाषाएँ:

- चीनी और रूसी एससीओ सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषाएं हैं।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA